(ङ) टिहरी परियोजना के निर्माण में अब रूस से भागीदारी की कितनी प्रतिशत होने का अनुमान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सिमनभाई पटेल): (क) से (ङ) टिहरी जल विद्युत परियोजना (2×100 मे०वा०) को प्रारम्भ में तत्कालीन सोवियत संघ सरकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से टर्न-की आधार पर तीन चरणों में पूरा करने क्रियान्वित करने की योजना थी। तथापि, सोवियत संघ के विघटित हो जाने से टिहरी परियोजना के लिए सोवियत रूस की सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह निर्णय लिया गया है कि उपलब्ध घरेलू संसाधनों एवं विदेशी वित्तपोषण के जरिये मशीनरी एवं उपस्कर प्राप्त करके चल रही टिहरी जल विद्युत परियोजना (1000 मे०वा० (टिहरी कामप्लैक्स का चरण-1) का सिविल निर्माण कार्य जारी रखा जाए।

निर्माणाधीन टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्कर सप्लाई करने और वित्त पोषण करने हेतु एक एशियन कंसोर्टियम, जिसमें रूस और उक्रेन के विनिर्माता शामिल हैं, ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव के बारे में टिहरी जल विद्युत विकास निगम, जोकि परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है, से द्वारा बातचीत की जा रही है, लेकिन टीएचडीसी की संतुष्टि के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कार्य निष्पादन गारंटी उपलब्ध कराए जाने में कंसोर्टियम द्वारा व्यक्त की गई असमर्थता को मुद्देनजर रखते हुए, उनके आगे लिए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता

5380. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त विद्युत क्षमता उत्पन्न की गई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1995 के अन्त तक देश में विभिन्न राज्यों में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए संस्थापित क्षमता का पूर्णतया उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1994 के दौरान इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए संस्थापित विद्युत क्षमता की कितनी औसत प्रतिशतता का प्रयोग किया गया;

(ङ) क्या यह भी सच है कि पूर्ण संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने की स्थिति में विद्युत उत्पादन की लागत हमेशा अधिक होती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती उर्मिला सिमनभाई पटेल): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31.01.95 की स्थिति के अनुसार यूटिलिटियों के अधीन विद्युत संयंत्रों की कुल अखिल भारतीय अधिष्ठापित क्षमता 78932.41 मे०वा० थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात अर्थात् क्षमता समुपयोजन का प्रतिशत नीचे दिया गया है:—

राज्य	पी०एल०एफ (%)
दिल्ली	66.0
हरियाणा	44.7
राजस्थान	75.6
पंजाब	56.7
उत्तर प्रदेश	58.8
गुजरात	61.3
महाराष्ट्र	61.1
मध्य प्रदेश	68.5
आन्ध्र प्रदेश	74.9
कर्नाटक	64.9
तमिलनाडु	64.7
बिहार	20.0
उड़ीसा	29.0
पश्चिम बंगाल	57.0
असम	26.7

(ङ) और (च) अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न कारणों जैसे, संयंत्र अनुरक्षण, उपस्कर खराबी बंदिशों और प्रणाली भार परिवर्तनों के कारण ताप विद्युत केन्द्रों का

पूर्ण क्षमता समुपयोजन प्रायः संभव नहीं होता। इसलिए, इस प्रकार की स्थिति में विद्युत उत्पादन की लागत अलग-अलग केन्द्रों में भिन्न-भिन्न होती है।

विद्युत उत्पादन के लिए समझौते

5381. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सरकार ने 1 अप्रैल, 1995 तक विद्युत उत्पाद के सम्बन्ध समझौते किये हैं;

(ख) उन कम्पनियों के देशवार नाम क्या हैं जोकि भारत में विद्युत क्षेत्र में पूंजी-निवेश करने के लिए पहल कर रही हैं और प्रत्येक देसी कम्पनी द्वारा कितनी धन-राशि का निवेश किया जाएगा; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सिंगनभाई पटेल): (क) विद्युत उत्पादन के बारे में सरकार से सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) व (ग) उन विद्युत कम्पनियों, जिन्होंने अपनी अभिप्रापित क्षमता और अनुमानित लागत समेत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निवेश करने की रुचि प्रकट की है, उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[देखिए परिशिष्ट 173 अनुपत्र सं० 116]

डीजल पर आधारित विद्युत संयंत्र

5382. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल पर आधारित कुछ विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर होने वाली अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से सम्बद्ध कार्य कब तक चालू किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सिंगनभाई पटेल): (क) से (ग) डीजल आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के उन प्रस्तावों का ब्यौरा, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आपूर्ति स्वीकृति हेतु प्राप्त की गई है, निम्नवत है:—

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (रु०)	अभिव्यक्ति
1. कोझिकोडे डीजल जेनेरेटिंग प्रोजेक्ट केरल (120 मे०वा०)	355.00 करोड़	इन स्कीम को के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
2. बम्बूलसैट डीजल जेनेरेटिंग प्रोजेक्ट,साउथ अण्डेमान्स (50 मे०वा०)	69.9 करोड़	इन स्कीम को भी-के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
3. केलालंका डीजी सेट्स विस्तार, कर्नाटक (47 मे०वा०)	124.10 करोड़	
4. कासारगोडे डीजल जेनेरेटिंग पावर प्रोजेक्ट, केरल (60 मे०वा०)	180.8 करोड़	
निजी क्षेत्र		
5. ग्वालियर डीजल जेनेरेटिंग प्रोजेक्ट (126. मे०वा०) मध्य प्रदेश	524.05 करोड़	
6. सामायानाल्लूर डीजल जेनेरेटिंग प्रोजेक्ट (100 मे०वा०) तमिलनाडु	384.00 करोड़	